

UG study material for students of History

Subject : History

class : UG Semester IV

Paper : MJC-05

Topic : यत्ना की प्रशासनिक व्यवस्था-II

By : Dr. Rajiv Nayan
Associate Professor,
Deptt. of History,
Jagjivan College, Ara.

चीलों की प्रशासनिक व्यवस्था - II

चील सम्राटों ने अपनी प्रबल लैतिक-शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य निर्मित किया तथा इनकी नीलैतिक शक्ति तो अभूतपूर्व थी ही। अपनी इसी शक्ति के इस्तेमाल से उन्होंने दक्षिणपूर्व एशिया पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। इतिहास, अश्वारोही तथा पैदल सैनिकों के प्रतिरक्त मोर्चेना सुव्यवस्थित ढंग से संगठित थी। सेना कड़गाम या पडेविडु (प्लावनी) में रहती थी। सैनिकों के समुचित प्रशिक्षण, अभ्यास तथा अनुशासन पर बल दिया जाता था। इतिहास के तथ्य साक्षी हैं कि साठ हजार का विशाल इतिहास तथा इठ लाख पैदल सैनिक चील सेना में थे। सम्राट के उपविगत अंगरक्षक को 'वेडेवकार' कहा जाता था।

चीलों की न्याय-व्यवस्था के विषय में पाऊ-कुआ लिखता है कि "जब कोई अपराध करता है तब दरबार का कोई मंत्री उसे दंड दे सकता है। सामान्य अपराध में दंड-प्रहार तथा जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती थी।" दक्षिण भारत के अभिलेखों से इस काल के स्थानीय शासन का पता चलता है। स्थानीय शासन में पायी जानेवाली अजाधारण क्षमता इस युग की विशेषता थी।

गाँव एक प्रशासकीय इकाई हुआ करता था, और यहाँ तक चाँल प्रशासन तथा गुप्त प्रशासन में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं था। परन्तु ग्राम-प्रशासन की प्रकृति में अवश्य ही काफी अंतर था। उस समय में गाँवों को दो गणीय घट स्वायत्तता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चाँल अधिकारी गाँवों के मामलों में प्रशासकों के रूप में नहीं, बल्कि परामर्शदाताओं और प्रेषकों के रूप में भाग लेते थे। इसके ऊपरी स्तर पर होनेवाले राजनीतिक परिवर्तनों के बहुत अधिक हस्तक्षेप के बिना स्थानीय इन्तति और विकास निरंतर होने रहे, और अंशतः यही कारण है कि इस उपमहाद्वीप के अन्य भागों की तुलना में तमिल प्रदेश में अधिक व्यापक सांस्कृतिक निरंतरता देखी जा सकती है।

इस काल में विकसित होने वाली ग्राम स्वायत्तता के पीछे आधारभूत मान्यता यह थी कि प्रत्येक गाँव का शासन स्वयं ग्रामीणों द्वारा ही होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए ग्रामसभा का संगठन होता था और इसी सभा में सत्ता निहित होती थी। बड़े गाँवों में, जहाँ ग्रामीण संगठन अधिक जटिल होता था, विभिन्न प्रकार की समारं होती थीं, जिनमें सदस्यता

की भूमिकाओं के अनुसार एक ग्रामीण दो या अधिक
 समूहों का सदस्य हो सकता था। गाँव हमलों में
 बाँटा जा सकता था और प्रत्येक हमला अपने सदस्यों
 की एक समूह बना सकता था। जहाँ तक इन समूहों
 में सदस्यता का प्रश्न है, इसके सदस्य व्यावसायिक
 समूहों के प्रतिनिधि; जैसे - बड़ई, पुनार, मोहार
 भादि, भयवा ग्राम के अन्य कार्य, जैसे - स्थानीय
 मंदिर की देख-भाल करने वाले समूह में से कुछ
 लोग हो सकते थे। इन विविध समूहों के परस्पर
 संबंध गाँव के सामाजिक जीवन का आधार होता
 था। इन छोटे-छोटे समूहों के अतिरिक्त एक
 महासभा भी होती थी।

इस महासभा में अधिकांश स्थानीय
 निवासी होते थे और इनकी तीन श्रेणियाँ होती थीं :
 'उर' में एक साधारण ग्राम के करदाता सदस्य रहते
 थे; 'सभा' में केवल ग्राम के ब्राह्मण निवासी होते
 थे भयवा यह 'सभा' केवल इन ग्रामों में होती थी
 जो ब्राह्मणों को दान देने वाले होते थे, और अंत
 में 'नगरम' सामान्यतः व्यापारिक केन्द्र में होते
 थे; क्योंकि ये पूर्णतया व्यापारिक दृष्टिों की रक्षा के
 लिए होते थे। कुछ गाँवों में 'उर' और 'सभा' साथ-
 साथ होती थी।

उत्तरमेखर के 919 ई० तथा 929 ई० के दो
 पत्रों के स्थानीय 'महासभा' की कार्य संचालन-प्रणाली

पर पर्चा प्रकाश पड़ता है। 'वारिचम' (कार्यकारिणी लक्ष्मि) की लक्ष्मता के सिद्धे 35 से 70 वर्ष की आयु वाले ऐसे षष्ठी का नामांकन होता था जिसके पाल भगभग एक-डेठ एक भूदि ही तथा जो अपनी भूदि पर बने मकान में रहने वाला हो। साथ ही, वह वैदिक मंत्रों का जानकार हो। तीन वर्षों तक लक्ष्मि में रह चुकने, हिलाव प्रस्तुत न करने, चोरी करने वाले तथा पाप-कर्मों के भागी षष्ठी नामांकन के लिए अपांग्य लक्षण होते थे। एक अभिनेता के ज्ञात होता है कि कभी-कभी चुनाव के निचम सम्राट के द्वारा निर्धारित किए जाते थे किन्तु, अधिकतर ग्रामलगा द्वारा ही इसके निर्धारण का प्रचलन था। 'वारिचम' की तीन लक्ष्मियों में से एक उपवन (गौतमावारिचम), जलाशय (हरिवारिचम), स्वर्ण-लंबंधी लक्ष्मि (पनवारिचम) आदि लक्ष्मियाँ निर्दिष्ट होती थीं। किन्तु प्रत्येक गाँव में लक्ष्मियों की संख्या एकलमान नहीं होती थीं। महालगा को 'पैरु गुरि', इसके लक्ष्मियों को 'पैरु-मुक्कल' तथा लक्ष्मि के लक्ष्मियों को 'वारिचमपैरुमुक्कल' कहा जाता था। लगा की वैदिक गाँव के मन्दिर वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी। लार्कजत्रिक भूदि पर 'महालगा' का स्वामित्व होता था, साथ ही षष्ठीगत भूदि पर

भी इसका न्यायिक अधिकार था। जंगल को काटकर कृषियोग्य भूमि बनाना, गाँव की भूमि के उत्पादन तथा उस पर राजस्व का आकलन करने में केन्द्रीय अधिकारियों की लक्ष्यता करना, राजस्व वसूलना, कर न देने वाले की भूमि नीलाम करना, भूमि तथा छिपाई संबंधी भग्नों का फैसला करना आदि 'महालगा' के प्रमुख कार्य थे। गाँव के हित के लिये 'महालगा' कर (Tax) भी लगा सकती थी। न्याय क्षमति (न्यायतार) के तहत प्रायः अधिकारियों की लक्ष्यता के अपराध का पता लगती थी। इन ग्राम-लगाओं तथा सर्वसाधारण लोगों को 'ऊर' नामक संस्थाओं को 'पञ्च गणतंत्र' कहना सर्वथा उपयुक्त है।

पौर काल के प्रारंभ में गाँव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। अपने अन्त-वस्त्र की व्यवस्था यहाँ स्वयं होती थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होने के कारण अन्य क्षेत्रों से कोई उल्लेखनीय वित्तियमत नहीं था। उपारही शताब्दी से जब पौर काल में व्यापार का विस्तार बढ़ा तो नगरों का विकास हुआ और उसी के साथ-साथ गाँवों की स्थिति भी बढ़ली। ग्रामीण अर्थतंत्र में मुद्रा-प्रणाली का सूत्रपात हुआ।

निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि एक शक्तिशाली केन्द्रीय नियंत्रण एवं स्थानीय स्वशासन के साथ पौरों ने एक ऐसी राजनीतिक पद्धति का निर्माण किया जिसमें कठोरता के साथ-साथ जनकल्याण की भावना भी निहित थी।